आंध्र प्रभा लिमिटेड एवं अन्य

बनाम

सचिव, मद्रास यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स एवं अन्य

मई 4, 1967

[के. एन. वांचू, सी.जे. एवं जी.के. मित्तर, जे.]

औद्योगिक विवाद-समाचार पत्र प्रकाशित करने वाली कंपनी-की बिक्री अन्य कंपनियों को समाचार पत्र प्रकाशित करने के अधिकार-कब बंद करने के समान है।

13 अप्रैल, 1959 को एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (पी) लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा यह संकल्प लिया गया कि कंपनी को अपने दैनिक और साप्ताहिक समाचार पत्रों के मुद्रण और प्रकाशन के मालिकाना अधिकार इंडियन एक्सप्रेस (मदुरै) (पी) लिमिटेड, मदुरै और आंध्र प्रभा (पी) लिमिटेड, विजयवाड़ा को बेचना चाहिए।खरीदार-कंपनियों में विक्रेता-कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष और उनके परिवार के सदस्यों के पास 4200 में से 4000 शेयर थे। 22 अप्रैल, 1959 को आंध्र प्रभा (पी) लिमिटेड और एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें यह सहमति बनी थी कि खरीदार-कंपनी द्वारा खरीदे गए प्रकाशनों के संबंध में विक्रेता-कंपनी द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों को उनकी सेवा की शर्तों में कोई

बदलाव किए बिना खरीदार कंपनी की सेवा में लिया जाएगा।एक्सप्रेस समाचार पत्रों के कर्मचारी जो विजयवाड़ा में कंपनी की बिक्री का विरोध कर रहे थे, इस आधार पर कि पहले चरण में आश्वासन दिया गया था कि समाचार पत्रों का प्रकाशन मद्रास से विजयवाड़ा में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, उन्हें विजयवाड़ा में कंपनी को बिक्री और उसके साथ सहमति के बारे में सूचित किया गया था।उन्हें यह भी सूचित किया गया कि जो श्रमिक विजयवाड़ा में खरीदार कंपनी में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे, उनकी सेवाओं को सामान्य शर्तों पर समाप्त कर दिया जाएगा क्योंकि एक्सप्रेस समाचार पत्रों के पास उन्हें देने के लिए कोई काम नहीं था। श्रमिकों ने तब हड़ताल की सूचना दी और 27 अप्रैल, 1959 से काम बंद कर दिया। 29 अप्रैल, 1959 को एक्सप्रेस समाचार पत्रों के प्रबंधन ने बंद करने की सूचना दी और कंपनी को बंद कर दिया और अगले दिन मद्रास सरकार ने औद्योगिक न्यायाधिकरण को दो प्रश्न भेजे, अर्थात् (1) क्या समाचार पत्र और साप्ताहिक का प्रकाशन विजयवाड़ा को हस्तांतरित करना उचित था, और (2) क्या हड़ताल और तालाबंदी उचित थी। हालांकि कंपनी ने 29 अप्रैल को समाचार पत्रों और साप्ताहिकों के प्रकाशन के अपने उपक्रम को बंद कर दिया क्योंकि उसके पास बहुत मूल्यवान संपत्ति थी, उसने कुछ व्यक्तियों को संपत्ति की देखभाल के लिए रखा, जिनमें से एक रिपोर्टर था, जो सम्पत्ति आैर मद्रास में टेलीप्रिंटर सेवा, जिसका उपयोग अक्टूबर 1959

के अंत तक मदुरै और विजयवाड़ा कंपनियों द्वारा किया जाता रहा, की देखभाल करने के लिए था।

ट्रिब्यूनल ने माना कि कथित का कोई सबूत नहीं था विजयवाड़ा में स्थानांतरित नहीं होने का आश्वासन दिया गया और हड़ताल अनुचित थी। हालाँकि, ट्रिब्यूनल ने कहा कि कारोबार की शुरुआत में निलंबन यानी 29 अप्रैल को तालाबन्दी थी, लेकिन वास्तविक रूप से अक्टूबर 1959 के अंत तक ही बंद हुआ।

इसकी अपील मजदूरों के साथ-साथ प्रबंधन ने भी इस अदालत को की।

निर्धारण किया गया: 29 अप्रैल को भी वास्तविक बंदी थी, मूल उपक्रम के फैलाव की योजना दुर्भावनापूर्ण नहीं थी। यदि हड़ताल न होती तो योजना को प्रभावी करने के लिए बंदी हो जाती योजना और हड़ताल ने केवल मामलों को प्रेरित किया। [912 सी-डी]

नई कंपनी जो एक स्वतंत्र कानूनी इकाई थी उसे सहायक कंपनी या बड़े का संगठन का लाभार्थी नहीं कहा जाएगा, केवल इसलिए कि, दोनों कंपनियों में एक व्यक्ति या परिवार था जो दोनों कंपनियों की नियति का मार्गदर्शन कर सकता है। इसके अलावा, तथ्य यह है कि उनमें एक रिपोर्टर भी था जो संपत्ति की देखभाल के लिए रखा गया था जो इस अनुमान की

ओंर नहीं जाता कि कंपनी ने अपने व्यवसाय को बंद नहीं किया है आैर तब तक जारी रखा जब तक कि वह चाहती थी। इसी प्रकार, कर्मचारी एवं भविष्य निधि अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी को 700 श्रमिकों के रोजगार की समाप्ति के बारे में सूचित करने में विफलता एक चूक थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि कर्मचारीगण कंपनी की सेवा में काम करते रहे। के संबंध में टेलीप्रिंटर सेवा, इसका भुगतान अक्टूबर तक कर दिया गया था तथ्य यह है कि मदुरै और विजयवाड़ा की कंपनियों ने इसका इस्तेमाल किया अक्टूबर 1959 के अंत तक अपने आप या अंदर नहीं होगा मामले की अन्य परिस्थितियों के साथ संयोजन इसे उचित ठहराता है निष्कर्ष यह है कि कंपनी ने टेलीप्रिंटर सेवा बरकरार रखी है अपने स्वयं के उपयोग के लिए. [914 बी-एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील 1965 की संख्या 1078 व 1079 और 1966 की 9।

1962 के औद्योगिक विवाद संख्या 1 में विशेष औद्योगिक न्यायाधिकरण, मद्रास के निर्णय दिनांक 31 जुलाई, 1963 से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

एनसी चटर्जी और आर. गणपति अय्यर, अपीलकर्ताओं के लिए (1965 के सीए नंबर 1078 और 1079 में) और उत्तरदातागण (1966 के सीए नंबर 9, में)।

अपीलकर्ता (1966 के सीए संख्या 9 में) और उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 (1965 के सीए संख्या 1078 और 1079 में) के लिए एस मोहन कुमारैनंगलम, एमके राममूर्ति, श्यामला पप्पू, नागरत्नम और मदन मोहन।

आर.त्यागराजन, प्रतिवादी संख्या 3 के लिए (1966 के सीए संख्या 9 में)।

न्यायालय का निर्णय मित्तर, जे. द्वारा सुनाया गया।

ये विशेष औद्योगिक न्यायाधिकरण, मद्रास द्वारा 31 जुलाई, 1963 को दिए गए एक फैसले के सामने तीन अपीलें हैं।जिस समय संदर्भ दिया गया था, उस समय इस विवाद के पक्षकार एक तरफ एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (पी) लिमिटेड के तहत कार्यरत श्रमिक और कर्मचारी और श्रमजीवी पत्रकार थे और दूसरी तरफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (पी) लिमिटेड, बाद में कंपनी के रूप में संदर्भित, मद्रास से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का स्वामित्व और प्रकाशन करती थी।इन्हें तीन समूहों में विभाजित किया जा सकता है।पहले समूह में इंडियन एक्सप्रेस (दैनिक), संडे स्टैंडर्ड (साप्ताहिक) और स्क्रीन (साप्ताहिक) शामिल थे: ये सभी अंग्रेजी

में प्रकाशित होते थे।दूसरे समूह में आंध्र प्रभा (दैनिक) और आंध्र प्रभा इलस्ट्रेटेड वीकली (साप्ताहिक) शामिल थे: ये तेलुगु भाषा में प्रकाशित होते थे।तीसरे समूह में दो पत्र दिनमणि (दैनिक) और दिनमणि कादिर (साप्ताहिक) शामिल थे: ये तमिल भाषा में थे।(राम नाथ गोयनका 1946 में गठित कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष थे। वह एक्सप्रेस न्यूज पेपर के निदेशकों में से एक भी थे) लिमिटेड जो दिल्ली में एक प्रेस और अखबार का स्वामित्व और नियंत्रण करती थी।ऐसा प्रतीत होता है कि मद्रास में समाचार पत्रों का समूह 1956 से पहले बहुत समृद्ध नहीं था। इसने उस वर्ष से काफी मुनाफा कमाना शुरू कर दिया था।

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10(1)(डी) के तहत 30 अप्रैल, 1959 को मद्रास सरकार द्वारा दिए गए संदर्भ में दो प्रश्न थे:

(1) क्या विजयवाड़ा में 'आंध्र प्रभा' और 'आंध्र प्रभा इलस्ट्रेटेड वीकली' के प्रकाशन को 'आंध्र प्रभा (पी) लिमिटेड' को स्थानांतरित करना उचित है और 'कर्मचारी और कामकाजी पत्रकार किस राहत के हकदार हैं?

(2) क्या 27 अप्रैल, 1959 से श्रमिकों और श्रमजीवी पत्रकारों की हड़ताल और उसके परिणामस्वरूप एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (पी) लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा की गई तालाबंदी उचित है और कर्मचारी किस राहत के हकदार हैं?

इसे बाद में 3 नवंबर, 1962 के एक आदेश द्वारा विशेष औद्योगिक न्यायाधिकरण को स्थानांतरित कर दिया गया जिसने निर्णय दिया है। हालाँकि उस तारीख से पहले यह मामला 1 मई, 1959 और 5 मई, 1959 को मद्रास उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं की अपील में इस न्यायालय में आया था, जिसमें धारा 10(3) के तहत दिए गए आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी और औद्योगिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में इस आधार पर विवाद पर फैसला सुनाया गया कि कोई तालाबंदी नहीं थी बल्कि कंपनी का कारोबार बंद था।इस न्यायालय ने एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स लिमिटेड प्रबंधन बनाम श्रमिकगण और स्टाफ ([1]) में यह माना कि क्षेत्राधिकार के बारे में प्रारंभिक जांच औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा ही उन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए जो प्रासंगिक और भौतिक हैं।

पार्टियों को जोड़ने के लिए श्रमिकों के आवेदन पर, आंध्र प्रभा लिमिटेड, इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (मदुरै) लिमिटेड और एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स लिमिटेड, एक सार्वजनिक कंपनी को विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष पार्टियों के रूप में जोड़ा गया था।

चूंकि विशेष न्यायाधिकरण को जिस विवाद पर फैसला देना था, वह कंपनी और उसके श्रमिकों के बीच इस तरह का पहला विवाद नहीं था, इसलिए कुछ तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है जो 2 अगस्त, 1962 के

इस न्यायालय के फैसले में पाए जाते हैं जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है।पूर्व निर्णय में न्यायालय के अनुसार यह कथन, पक्षों के बीच वर्तमान विवाद की पृष्ठभूमि बनाता है।मार्च 1957 में बोनस समेत कुछ बिंदुओं पर पार्टियों के बीच विवाद हो गया। इसे 1957 में एक अवार्ड के रूप में समाप्त होने वाले औद्योगिक निर्णय के लिए संदर्भित किया गया था।मार्च 1958 में कंपनी ने 69 श्रमिकों की छंटनी करने के अपने इरादे को अधिसूचित किया और इससे एक और विवाद खड़ा हो गया जिसे निर्णय के लिए भेजा गया। यूनियनों ने राज्य सरकार से कुछ शिकायतें कीं जिसके चलते राज्य के गृह मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।30 अक्टूबर, 1958 को कंपनी ने कर्मचारियों और कामकाजी पत्रकारों को नोटिस दिया कि वह 1 दिसंबर, 1958 से मद्रास में अपना व्यवसाय बंद करने जा रही है, अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाते हुए कि क्षम की ओर से लगातार श्रमिक परेशानियाँ और अनुशासनहीनता हो रही है। गृह मंत्री ने फिर हस्तक्षेप किया और इस बार सफलता मिली। 6 नवंबर, 1958 को मद्रास के श्रम आयुक्त की उपस्थिति में प्रबंधन और कर्मचारियों और पत्रकारों के बीच एक समझौता हुआ।समझौते की शर्तों को लिखित रूप में लिख दिया गया है और केवल वे जिन पर ध्यान दिया जा सकता है, हैं :-

(1)30-4-1958 को छंटनी किए गए सभी कर्मचारियों को सेवा की निरंतरता के साथ बहाल किया जाएगा।

(10)समझौते के मद्देनजर प्रबंधन बंद करने का नोटिस वापस ले लेगा और नोटिस बोर्ड पर इसकी घोषणा करेगा।

समझौता 2 1/2 वर्ष के लिए प्रभावी होना था।कार्यकर्ताओं के अनुसार, श्री गोयनका ने 6-11-1958 को आश्वासन दिया था कि वे उक्त अवधि के दौरान उल्लिखित किसी भी पत्र का प्रकाशन मद्रास से विजयवाड़ा में स्थानांतरित नहीं करेंगे।

पिछले अवसर पर, जब मामला इस न्यायालय के समक्ष था, इस आश्वासन का संदर्भ दिया गया था और इस न्यायालय ने माना था कि यह एक ऐसा विषय था जिस पर औद्योगिक न्यायालय को विचार करना होगा। प्रबंधन के अनुसार नवंबर 1958 में यह महसूस किया गया कि तेलुगु अखबारों का प्रकाशन विजयवाड़ा से किया जाना चाहिए।समाचार पत्रों के नियंत्रण के प्रसार के संबंध में प्रेस आयोग के सुझाव पर भी एक अतिरिक्त विचार किया जा रहा है।उस समय या उसके आसपास रामनाथ गोयनका की मंशा पर विचार किए बिना, हम उसके बाद की घटनाओं पर ध्यान दे सकते हैं।17 जनवरी, 1959 को कुछ प्रस्तावों पर विचार करने के लिए कंपनी के शेयरधारकों की एक असाधारण आम बैठक की सूचना दी गई। दरअसल यह बैठक 11 फरवरी, 1959 को हुई थी और पारित प्रस्तावों में से एक यह था कि कंपनी को विभिन्न समाचार पत्रों के मालिकों के रूप में कारोबार करना बंद कर देना चाहिए और इसके अनुसरण में कंपनी बॉम्बे,

मद्रास, मदुरै और दिल्ली में अपने विभिन्न प्रकाशनों को बंद या स्थानांतरित कर देगी और अन्य पार्टियों को बेच देगी और अपने मुद्रण संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरणों को बेच देगी, किराए पर दे देगी या अन्यथा निपटान करेगी तथा विभिन्न स्थानों पर अपने परिसरों को लाइसेंस देगी या पट्टे पर देगी। एक अन्य प्रस्ताव ने निदेशकों को अधिकृत किया विभिन्न प्रकाशनों को बंद करने या उन्हें बेचने व स्थानान्तरण करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं जैसा वे उचित समझें आैर एेसी कीमतों और शर्तों पर जिन्हें वे सर्वोत्तम समझें। कर्मचारियों को इसकी भनक लग गई होगी और एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स एम्प्लॉइज यूनियन के सचिव (एतद्पश्चात सचिव के रूप में संदर्भित) ने 31 मार्च, 1959 को कंपनी के अध्यक्ष को इस आशय का एक पत्र लिखा कि कर्मचारियों को यह पता चल गया है। आंध्र प्रभा का एक संस्करण शुरू करने के उद्देश्य से मद्रास में रोटरी मशीन की चार इकाइयों को नष्ट कर दिया गया और विजयवाड़ा ले जाया गया।आंध्र प्रभा को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को छोड़ने के लिए गृह मंत्री के समक्ष दिए गए कथित आश्वासन का भी संदर्भ दिया गया था और अभिभाषक के साथ चर्चा के लिए कहा गया था।ऐसा प्रतीत होता है कि 2 अप्रैल को इस पत्र का उत्तर आया था जो हालांकि रिकॉर्ड में शामिल नहीं है।13 अप्रैल, 1959 को कंपनी के निदेशक मंडल ने कुछ प्रस्ताव पारित किये।उनमें से एक यह था कि कंपनी

बेचेगी और हस्तांतरित करेगी और इंडियन एक्सप्रेस (मदुरै) (पी) लिमिटेड एक चालू संस्था के रूप में, इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाले अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र के मदुरै संस्करण के मुद्रण और प्रकाशन के मालिकाना अधिकार खरीदेगी। अंग्रेजी साप्ताहिक का मदुरै संस्करण संडे स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है और तमिल दैनिक का मदुरै संस्करण दिनमणि (रविवार संस्करण सहित) के नाम से जाना जाता है।एक और प्रस्ताव इस आशय से पारित किया गया कि कंपनी बेचेगी और आंध्र प्रभा (पी) लिमिटेड विजयवाड़ा एक चालू संस्था के रूप में मुद्रण और प्रकाशन के मालिकाना अधिकार आंध्र प्रभा और आंध्र प्रभा इलस्ट्रेटेड वीकली साथ में खरीदने के खरीदेगी, इस विकल्प के साथ कि मुद्रण का अधिकार कंपनी को, संडे स्टैंडर्ड के रूप में जाने जाने वाले अंग्रेजी अखबार को आंध्र प्रदेश राज्य में प्रसार के लिए केवल 'मसौदा समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों' पर संपादित और प्रकाशित करें।तीसरा संकल्प इस आशय का था कि कंपनी मसौदा समझौते की अनुसूची में निर्धारित मशीनरी की वस्तुओं को आंध्र प्रभा (पी)-लिमिटेड विजयवाड़ा को ड्राफ्ट समझौते में निर्धारित शर्तों पर 1,75,000/- रु. पर बेच देगी।15 अप्रैल, 1959 को कंपनी और आंध्र प्रभा (पी) लिमिटेड के बीच वास्तव में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत विक्रेता बेचने के लिए सहमत हो गया था और खरीदार जल्द से जल्द अनुसूची में निर्धारित सामान खरीदने के लिए जितना सुविधाजनक

हो एवं क्रेता को मशीनरी मिलने के एक सप्ताह के भीतर 1,75,000/- रु. की राशि देय होगी।20 अप्रैल को, 1959 में मद्रास यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के महासचिव ने कंपनी के निदेशक को पत्र लिखकर शिकायत की कि लेखक ने 31 मार्च के पत्र में उठाए गए मुद्दे के संबंध में कुछ नहीं सुना है। पत्र में यह दर्ज किया गया कि पत्रकारों को यह नहीं बताया गया था कि प्रबंधन ने क्या करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन उन्होंने सुना है कि आंध्र प्रभा (पी) लिमिटेड नामक एक नई कंपनी विजयवाड़ा में पंजीकृत हुई थी और इसे विभाजित करने की व्यवस्था की जा रही थी। मद्रास के अन्य दो अखबार, इंडियन एक्सप्रेस और दीनामणि को दो अलग-अलग कंपनियों में बदल दिया गया। लेखक के मुताबिक इससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी. उसी दिन, मद्रास यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने एक बैठक में आंध्र प्रभा दैनिक और आंध्र प्रभा इलस्ट्रेटेड वीकली को विजयवाड़ा में एक नई कंपनी को बेचने की घोषणा करने और प्रभावित करने में प्रबंधन की कार्रवाई की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जो गुप्त रूप से किया गया था, और जैसा कि इसके परिणामस्वरूप संबंधित सभी कर्मचारियों को नई कंपनी द्वारा समाहित नहीं किया जा सकेगा एक शिकायत यह भी की गई थी कि बिक्री वास्तव में बेनामी थी और धमकी दी गई थी कि जब तक प्रबंधन "दुर्भावनापूर्ण तरीके से मद्रास प्रतिष्ठान को बंद करने और तोड़ने और बेनामी कंपनियों को कथित बिक्री के उपरोक्त

पाठ्यक्रम से बाज नहीं आता, तब तक कर्मचारियों को संकल्प के तहत गठित संयुक्त कार्रवाई समिति द्वारा तय की जाने वाली तारीख से हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर किया जाएगा।" कमेटी ने कहा कि जब तक 72 घंटे के भीतर प्रस्ताव में उल्लिखित मामलों के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं भेजा जाता, संयुक्त कार्रवाई समिति, कर्मचारियों के हड़ताल के लिए आह्वान के जनादेश को पूरा करने के लिए मजबूर होगी।

22 अप्रैल, 1959 को आंध्र प्रभा (पी) लिमिटेड और कंपनी के बीच लिखित रूप में एक समझौता हुआ था कि पहली नामित कंपनी खरीदने के लिए सहमत हो गई थी और कंपनी एक चालू चिंता के रूप में मालिकाना अधिकारों को बेचने के लिए सहमत हो गई थी। आंध्र प्रभा (तेलुगु दैनिक) और आंध्र प्रभा इलस्ट्रेटेड वीकली के संपादकों, मालिकों आदि के साथ-साथ विक्रेता से अंग्रेजी समाचार पत्र, इंडियन एक्सप्रेस और अंग्रेजी साप्ताहिक द सन्डे स्टेण्डर्ड को मुद्रित करने, संपादित करने और प्रकाशित करने का अधिकार खरीदने का विकल्प भी शामिल है। आंध्र प्रभा और आंध्र प्रभा मुसट्रेड वीकली में मालिकाना हक की बिक्री के लिए प्रतिफल 25,000/- रुपये तय किया गया था। समझौते के खंड 11 में प्रावधान है कि:

> "उपरोक्त दो प्रकाशनों के संबंध में विक्रेता द्वारा नियोजित सभी कर्मचारियों को अधिग्रहण की तारीख से क्रेता कंपनी की सेवा में ले लिया जाएगा।"

खंड 12 में प्रावधान है कि दोनों उपक्रमों का स्थानांतरण इस शर्त पर होगा कि प्रत्येक कामगार और कर्मचारी जो पदभार ग्रहण करने की तारीख से ठीक पहले विक्रेता के उक्त उपक्रम में एक वर्ष से कम समय तक निरंतर सेवा में रहे थे, उन्हें कार्यभार ग्रहण कर लिया जाएगा। क्रेता को ऐसी तारीख से नियम और शर्तों पर लागू किया जाएगा कि कामगारों और कर्मचारियों की सेवाएं इस तरह के स्थानांतरण से बाधित नहीं हुई हैं और न ही मानी जाएंगी और इसके बाद कामगारों और कर्मचारियों पर लागू नियम और शर्तें लागू होंगी। ऐसा स्थानांतरण किसी भी तरह से उनके लिए स्थानांतरण से पहले लागू होने वाले लाभ से कम अनुकूल नहीं होगा और क्रेता श्रमिकों और कर्मचारियों को, छंटनी की स्थिति में, इस आधार पर मुआवजा देने के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होगा कि एेसे स्थानान्तरण से उसकी सेवाएं निरंतर एवं अबाधित रही हैं। 23 अप्रैल, 1959 को कंपनी के निदेशक ने संयुक्त कार्रवाई समिति को इस आशय का पत्र लिखा कि प्रबंधन ने आंध्र प्रभा दैनिक और आंध्र प्रभा इलस्ट्रेटेड वीकली के संपादन, प्रकाशन आदि का अधिकार विजयवाड़ा में एक नई कंपनी को बेच दिया है। इसका कारण बताते हुए कहा गया कि यह तेलुगु भाषी लोगों के हित में है कि इसे तेलुगु केंद्र से उत्पादित और प्रकाशित किया जाना चाहिए। दोनों समाचार पत्रों के व्यवसाय से जुड़े सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को नई कंपनी द्वारा समाहित करने के संबंध में

नियम और शर्तों का भी उसमें उल्लेख किया गया था। अंततः, यह कहा गया था कि ऐसे कर्मचारी जो विजयवाड़ा जाने के इच्छुक नहीं हैं, कंपनी के साथ उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी क्योंकि कंपनी उन्हें देने के लिए कोई काम नहीं करेगी, लेकिन उन्हें उनके सभी बकाया का भुगतान किया जाएगा। 24 अप्रैल, 1959 को संयोजक, संयुक्त कार्रवाई समिति ने निदेशक के 23 वें उत्तर को अत्यधिक असंतोषजनक बताया और कहा कि इस आशय का एक प्रस्ताव अपनाया गया था कि कर्मचारी 24 घंटे की समाप्ति के बाद किसी भी समय हड़ताल पर जायेंगे। अगले दिन निदेशक ने यूनियन को सूचित किया कि प्रस्तावित हड़ताल अवैध और अनुचित होगी। 27 अप्रैल को संयोजक ने निदेशक को पत्र लिखकर कहा कि प्रबंधन ने मद्रास से तीन समाचार पत्रों के प्रकाशन के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने की उनकी मांग को खारिज कर दिया है। विशेषकर आंध्रप्रभा. इसके अलावा तोड़फोड़ और धमकियों और गिरफ्तारी के झूठे आरोप लगाए गए और परिणामस्वरूप कर्मचारियों को 24 अप्रैल के निर्णय को प्रभावी करने यानी हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर किया गया। हालाँकि, निगरानी और वार्ड कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहने का निर्देश दिया गया था।

इस स्तर पर यह नोट करना आवश्यक है कि प्रबंधन के अनुसार 26 अप्रैल, 1959 को तोड़फोड़ और घोर अनुशासनहीनता के कुछ कार्य किए गए थे, अर्थात् दिनमणि मामले के एक पूर्ण पृष्ठ और दो गैलियों को विकृत

और नष्ट करना और स्विच को हटाना। तीन मोटर कारों की चाबियाँ कार्यालय भवन के सामने छोड़ दी गईं। ट्रिब्यूनल के समक्ष रामनाथ गोयनका के बयान के अनुसार:

> "पूरे 28 अप्रैल के दौरान मजदूरों ने कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और कार्यालय भवन में कर्मचारियों के प्रवेश और निकास को रोका।फिर मैंने इसे बंद करने का फैसला किया और द हिंदू के माध्यम से एक बयान जारी कर सभी को इसकी जानकारी दी।"

उपरोक्त आशय का एक नोटिस 27 तारीख को कंपनी के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया गया था और इसकी एक प्रति निदेशक द्वारा संयोजक को भेजी गई थी।

27 अप्रैल को शाम 4.30 बजे कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो गई और सभी पत्रों का प्रकाशन बंद कर दिया गया. उपरोक्त को सूचना: इंडियन एक्सप्रेस दिनमणि और आंध्र प्रभा के संबंध में द हिंदू में प्रभाव दिया गया था। 29 अप्रैल को द हिंदू में क्लोजर नोटिस प्रकाशित किया गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि प्रबंधन ने 23 अप्रैल को पत्र द्वारा श्रमिकों को सूचित किया था कि उन्होंने आंध्र प्रभा और आंध्र प्रभा इलस्ट्रेटेड वीकली के संपादन, मुद्रण और प्रकाशन का अपना अधिकार

विजयवाड़ा कंपनी को बेच दिया था। इस नोटिस में दोनों कंपनियों के बीच श्रमिकों को लेकर हुए समझौते का सार भी बताया गया था. श्रमिकों को सूचित किया गया था कि प्रबंधन ने मद्रास में सभी सात समाचार पत्रों के उपक्रम और प्रकाशन को तत्काल प्रभाव से बंद करने और श्रमिकों और श्रमजीवी पत्रकारों की सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया ह। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि धारा 25 एफ के अन्तर्गत निर्धारित नोटिस एवं अधिनियम के तहत निर्धारित मुआवजे के एवज में एक महीने के वेतन के अतिरिक्त, उन्हें जिस अवधि में उन्होंने कार्य किया, के लिए वेतन का भुगतान किया जाएगा।इस प्रकार, मुआवज़े की राशि 7 लाख रु. का वास्तव में भुगतान बाद में किया गया।

30 अप्रैल को प्रबंधन ने घटनाक्रम के संबंध में पुलिस आयुक्त को सूचित किया और बंद करने के संबंध में हिंदू में एक और नोटिस प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया कि अधिकांश मशीनरी पहले ही नकदी के लिए बेच दी गई थी और कंपनी की इमारत किराए के लिए विज्ञापित की गई थी उसी दिन मद्रास सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10(3) के तहत एक नोटिस जारी कर हड़ताल और तालाबंदी जारी रखने पर रोक लगा दी। इसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय में पहले से उल्लिखित दो रिट याचिकाएँ दायर की गईं।

अगस्त 1962 में इस न्यायालय द्वारा मामले का निर्णय लिए जाने के बाद, विशेष औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया था।जिनसे पहले रामनाथ गोयनका सहित कुछ गवाह थे जाँच की गई और बड़ी संख्या में दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। पहले अंक के संबंध में केंद्रीय प्रश्न यह था कि क्या रामनाथ गोयनका ने नवंबर 1958 में मौखिक आश्वासन दिया था कि मद्रास से किसी भी समाचार पत्र के प्रकाशन का स्थान 2 साल के लिए विजयवाड़ा में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। न्यायाधिकरण ने मौखिक और दस्तावेजी दोनों तरह के साक्ष्यों की बहुत विस्तार से जांच की और कहा कि यह संतुष्ट नहीं था कि रामनाथ गोयनका ने उन्हें कोई मौखिक आश्वासन दिया था। न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि मामले की परिस्थितियों से प्रकृति के आश्वासन का अनुमान इस परिणाम के साथ नहीं लगाया जा सकता है कि पहले मुद्दे के पहले भाग का उत्तर इस आवश्यक परिणाम के साथ सकारात्मक रूप से दिया गया था कि इन दोनों प्रकाशनों के हस्तांतरण के कारण श्रमिकों को किसी भी राहत का हकदार नहीं ठहराया जा सकता है।

तीन अपीलों में से, पहली दो आंध्र प्रभा लिमिटेड और इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (मदुरै) लिमिटेड द्वारा हैं और दूसरी एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स लिमिटेड नामक सार्वजनिक कंपनी द्वारा है। तीसरी अपील इसके प्रबंधन के खिलाफ एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा है।

हमारे सामने यह दिखाने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि मौखिक आश्वासन या उसके संबंध में परिस्थितियों से निकाले जाने वाले सम्मेलन के अभाव के बारे में ट्रिब्यूनल का निष्कर्ष गलत था। कर्मचारियों की ओर से तर्क का सार यह था कि वास्तव में कोई समापन नहीं हुआ था, बल्कि मूल कंपनी से सहायक कंपनियों में स्थानांतरण प्रभावी था और इस संबंध में केज़ कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी बनाम इसके कर्मी([1]) में इस अदालत के फैसले और श्रमिक बनाम दाहिंगेपार टी एस्टेट में पिछला निर्णय ([2]) पर भरोसा किया गया था। केज़ कंस्ट्रक्शन कंपनी([1]) मामले में एक निजी लिमिटेड कंपनी को एक मालिकाना कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को जारी रखने और चलाने के लिए शामिल किया गया था। पूर्व मालिक, उसकी पत्नी और पूर्व व्यवसाय में कार्यरत प्रबंधक नई कंपनी के पांच निदेशकों में से तीन थे। नई कंपनी द्वारा कुछ पूर्व कर्मचारियों को सेवा में बनाए रखने से इनकार करने के संबंध में विवाद को निर्णय के लिए एक औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास भेजा गया था। कामगारों की ओर से यह तर्क दिया गया कि मालिक द्वारा कथित तौर पर बंद करना सही या वास्तविक नहीं था और नई कंपनी मालिक के हित में उत्तराधिकारी थी और इसलिए पूर्व कामगारों को रोजगार देना जारी रखने के लिए बाध्य थी। यह भी तर्क दिया गया कि वास्तव में तालाबंदी थी और संबंधित कर्मचारी बहाली के हकदार थे। ट्रिब्यूनल ने पाया कि 'कथित वित्तीय आधार पर पूर्व

व्यवसाय को बंद करना सही नहीं था, और कंपनी, हालांकि कानून में एक अलग इकाई थी, का गठन एक अलग नाम के तहत पूर्व व्यवसाय को जारी रखने और जारी रखने के लिए किया गया था और कंपनी ने इनकार कर दिया। कुछ पुराने कर्मचारियों को काम पर लगाना तालाबंदी के समान था जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की बहाली का आदेश दिया गया। कंपनी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील खारिज कर दी गई। इस न्यायालय ने माना कि उसके पहले जैसे मामले का निर्णय मुख्य रूप से कानून के सार बिंदु पर विचार करके नहीं किया जा सकता है - जैसे कि व्यवसाय में उत्तराधिकारी पूर्व मालिक द्वारा नियोजित श्रमिकों को रोजगार में जारी रखने के लिए बाध्य है या नहीं। न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज तथ्य के भौतिक निष्कर्षों के संबंध में अवार्ड की वैधता पर प्रश्न नहीं किया जा सका।

दहिंगियापार टी एस्टेट मामले([2]) में दहिंगियापारा चाय कंपनी (विक्रेता) और निखली जूट बेलिंग कंपनी लिमिटेड (क्रेता) के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत विक्रेता पूरी तरह से बेचने के लिए सहमत हुआ और क्रेता 1 जनवरी, 1954 से संपूर्ण चाय बागान जिसे दाहिंगेपार चाय बागान के रूप में जाना जाता है, उसके सभी बागानों, झाड़ियों, मशीनरी और साज समान आदि सहित 9,50,000/- पर या रुपये की राशि के लिए खरीदने के लिए सहमत हुआ। क्रेता के पास स्टाफ के ऐसे सदस्यों

को लेने का विकल्प था क्योंकि वह अपने पूर्ण विवेक से इसे चलाने के लिए उपयोगी और पर्याप्त समझेगा। क्रेता द्वारा चुने गए स्टाफ के सदस्यों को नई नियुक्ति दी जाएगी और बोनस, ग्रेच्युटी आदि सहित उनकी पिछली सेवाओं के लिए कोई भी दायित्व विक्रेता के खाते पर होगा। जो विवाद निर्णय के लिए भेजा गया था, वह यह था कि क्या प्रबंधन का स्थानांतरण चाय बागान के कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर सकता है और क्या स्थानांतरण का समझौता कर्मचारियों के सदस्यों को सेवा के मूल अनुबंधों के तहत सेवा के उनके अधिकार और उनकी सेवाओं की निरंतरता से उन्हें वंचित कर देगा। दूसरा सवाल यह था कि क्या निवर्तमान प्रबंधन का उस समय से कर्मचारियों के सदस्यों की सेवाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव उचित था जब चाय बागान का प्रबंधन बदल गया था और क्या आने वाले प्रबंधन की सेवा की निरंतरता बनाए रखने से इनकार करना उचित था? ट्रिब्यूनल ने पाया कि बगीचे को एक चालू संस्था के रूप में बेचा गया था, कि कर्मचारियों की सेवाएं 4 जनवरी, 1954 तक जारी रहीं, कि व्यापार के कारणों से या उसके कारण छंटनी की आवश्यकता नहीं थी और स्थानांतरण से कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं हो सकता था। परिणाम यह हुआ कि क्रेता द्वारा सेवा की निरंतरता बनाए रखने से इनकार करना उचित नहीं ठहराया गया। अवार्ड में निर्देश दिया गया कि पूर्व स्टाफ के वे सदस्य जिन्हें नए प्रबंधन द्वारा कार्यभार संभालने के समय से ही उद्यान में

सेवा से बाहर रखा गया था, लेकिन जो पिछली शर्तों पर अपने पूर्व पदों पर बहाल होने के इच्छुक होंगे, को उनकी सेवा शर्तों को उनके पूर्व पदों पर बहाल किया जाए और पुराने कर्मचारियों के उन सदस्यों को जिन्हें उद्यान में सेवा से बाहर रखा गया था और उन्होंने तब से कहीं और कोई रोजगार नहीं लिया है, उन्हें उनकी जबरन बेरोजगारी की अवधि के लिए वेतन का भुगतान किया जाए जो क्रेता के कहने पर हुआ था। श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए फैसले को रद्द कर दिया। अपील में इस न्यायालय ने इस बड़े प्रश्न को निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझा कि क्या, एक चालू संस्था के रूप में व्यवसाय के हस्तांतरण पर, आने वाला प्रबंधन बाहर जाने वाले प्रबंधन का उत्तराधिकारी बन जाता है और यदि हां, तो आने वाले प्रबंधन को किस हद तक ग्रेच्युटी बोनस आदि और सेवा की निरंतरता के लिए पहले से ही प्रोद्भूत अर्जित श्रम के अधिकार की पहचान करनी चाहिए । आगे यह देखा गया कि कानून के अमूर्त प्रश्न का निर्णय करना औद्योगिक न्यायाधिकरण का कार्य नहीं था, चाहे बिक्री के परिणामस्वरूप प्रबंधन के हस्तांतरण पर, श्रमिकों की सेवाएं स्वचालित रूप से समाप्त हो गईं।लेकिन यह माना गया कि एक विवाद था जिसे निर्णय के लिए भेजा जा सकता था और संदर्भ सक्षम होने के कारण न्यायाधिकरण के पास इसमें जाने का अधिकार क्षेत्र था और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा

औद्योगिक न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को विस्थापित करने का कोई कारण नहीं था।

यह ध्यान दिया जाएगा कि ये दो निर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन से पहले धारा 25 एफएफ और धारा 25 एफएफएफ को शामिल करके दिए गए थे । अब दो धाराएं ऐसे मामलों को नियंत्रित करती हैं। धारा 25 एफएफ के तहत जहां स्वामित्व या किसी उपक्रम का प्रबंधन, चाहे समझौते द्वारा या कानून के संचालन द्वारा, उस उपक्रम के संबंध में नियोक्ता से एक नए नियोक्ता को स्थानांतरित किया जाता है, प्रत्येक कर्मचारी जो ऐसे स्थानांतरण से ठीक पहले उस उपक्रम में कम से कम एक वर्ष तक निरंतर सेवा में रहा हो धारा 25 एफ के प्रावधानों के अनुसार नोटिस और मुआवजे का हकदार होगा मानो काम करने वाले की छँटनी कर दी गई हो। हालाँकि, यह धारा किसी कर्मचारी पर लागू नहीं होती है यदि उसकी सेवा इस तरह के स्थानांतरण से बाधित नहीं हुई है, स्थानांतरण के बाद उसकी सेवा के नियम और शर्तें किसी भी तरह से स्थानांतरण से ठीक पहले उस पर लागू की तुलना में कम अनुकूल नहीं हैं और नए नियोक्ता, ऐसे स्थानांतरण की शर्तों के तहत, कामगार को उसकी छंटनी की स्थिति में इस आधार पर मुआवजा देने के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी है कि उसकी सेवा निरंतर रही है और स्थानांतरण से बाधित नहीं हुई है।

एस के तहत धारा 25 एफएफएफ (1) जहां किसी भी कारण से कोई उपक्रम बंद हो जाता है, प्रत्येक कामगार जो ऐसे बंद होने से ठीक पहले उस उपक्रम में कम से कम एक वर्ष तक निरंतर सेवा में रहा हो, उपधारा (2) 25F के प्रावधानों के अधीन, के प्रावधानों के अनुसार नोटिस और मुआवजे का हकदार होगा मानो कामगार की छँटनी कर दी गई हो। हमें उप-धारा से कोई सरोकार नहीं है। (2) इस मामले में. परिणाम यह है कि यदि वास्तव में कोई बंद है, धारा 25 एफएफएफ कार्यान्वयन में आ जाएगा. इस मामले में, हालांकि, यह कहा जाना चाहिए कि नई कंपनी, आंध्र प्रभा (पी) लिमिटेड दो प्रकाशनों के संबंध में विक्रेता द्वारा नियोजित समय पर सभी कर्मचारियों को कार्यभार संभालने की तारीख से लेने के लिए सहमत हुई। उनकी सेवा की निरंतरता और एक ही अवधि में कोई व्यवधान और शर्तें पहले जैसी हैं.

रामनाथ गोयनका द्वारा उपक्रम के एक हिस्से को विजयवाड़ा और दूसरे हिस्से को मदुरै में स्थानांतरित करने का मन बनाने के सटीक कारण पर उंगली उठाना असंभव है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्हें वास्तव में लगता था कि यदि विजयवाड़ा में मुद्रित और प्रकाशित किया जाए तो तेलुगु अखबार बेहतर प्रदर्शन करेंगे। यह भी हो सकता है कि वह समाचार पत्रों की बड़ी इकाइयों द्वारा देय वेतन के संबंध में प्रेस आयोग की सिफारिश को दरकिनार करना चाहते हों। फिर इसमें कोई संदेह नहीं हो

सकता कि उन्हें कर्मचारियों का आंदोलन पसंद नहीं आया और शायद उन्होंने सोचा कि इकाइयों के बिखराव से आंदोलन की गुंजाइश कम हो जाएगी। फरवरी 1959 में कंपनी के शेयरधारकों द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसार वह निस्संदेह इस संबंध में सभी कदम उठा रहे थे। निदेशक मंडल के प्रस्ताव और 15 अप्रैल 1959 को आंध्र प्रभा (पी) लिमिटेड को कुछ मशीनरी की बिक्री के समझौते के बाद अनुमति दी गई, 15 अप्रैल 1959 को प्रदर्शित होगा। कर्मचारी शायद इस बात से परेशान थे कि इस सब के संबंध में उनसे कोई सलाह नहीं ली गई थी। हालाँकि यह कहना संभव नहीं है कि 26 अप्रैल, 1959 को हुई तोड़फोड़ और अनुशासनहीनता की कथित हरकतें बहुत गंभीर प्रकृति की थीं, गोयनका ने ट्रिब्यूनल के समक्ष अपने साक्ष्य में कहा कि उनके कार्यालय के सामने मजदूरों के प्रदर्शन के बाद 28 अप्रैल को और कार्यालय भवन में कर्मचारियों के प्रवेश और निकास को रोकने के लिए उन्होंने मद्रास में अपना उपक्रम बंद करने का निर्णय लिया।

ट्रिब्यूनल के समक्ष साक्ष्यों पर, जिस पर हमारा ध्यान दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा आकर्षित किया गया था, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रबंधन ने कर्मचारियों को विश्वास में लिया होगा और उनके साथ उपक्रम के फैलाव की योजना पर चर्चा की होगी। हड़ताल अनुचित एवं विनाशकारी थी। भले ही 27 अप्रैल को कोई हड़ताल न हुई हो. हमें ऐसा लगता है कि फैलाव की

योजना को बाद में लागू किया गया होगा, हालांकि यह हड़ताल ही थी जिसने मामले को बिगाड़ दिया।

न्यायाधिकरण ने पाया है कि बंद तो किया गया था लेकिन यह अप्रैल 1959 में नहीं बल्कि नवंबर 1959 में हुआ था। पहुँचने पर इस निष्कर्ष पर न्यायाधिकरण ने कई कारकों पर भरोसा किया। इनमें से पहला यह है कि इंडियन एक्सप्रेस (मदुरै) लिमिटेड द्वारा दीनामणि प्रेस में आंध्र प्रभा इलस्ट्रेटेड वीकली मुद्रित किया जाने लगा और यह इंडियन एक्सप्रेस मदुरै (पी) लिमिटेड और आंध्र प्रभा (पी) लिमिटेड के बीच 30 सितंबर 1960 के एक समझौते के अनुसरण में माउंट रोड मद्रास में स्थित एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स लिमिटेड से संबंधित इमारतों के ब्लॉक में स्थित है। न्यायाधिकरण ने आगे पाया कि 2 सितंबर 1960 को एक्सप्रेस एस्टेट माउंट रोड मद्रास में स्थित एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (पी) लिमिटेड से संबंधित ऑफसेट रोटरी प्रेस और संबद्ध उपकरणों को इंडियन एक्सप्रेस मदुरै (पी) लिमिटेड को किराए पर लिया गया था। इससे न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि "आंध्र प्रभा दैनिक और आंध्र प्रभा इलस्ट्रेटेड वीकली के साथ-साथ इंडियन एक्सप्रेस मदुरै संस्करण और दिनमणि दैनिक संस्करण भी एक्सप्रेस एस्टेट मद्रास में ऑफ-सेट रोटरी प्रेस का उपयोग उन अवसरों पर कर सकते थे जब ऑफ-सेट रोटरी प्रेस का उपयोग तब तक आवश्यक हो गया था जब तक कि पूर्व के तहत मदुरै कंपनी को मशीनें किराए पर एम-

46 के तहत नहीं ली गई थीं। हमारी राय में एक्सप्रेस एस्टेट मद्रास में ऑफ-सेट रोटरी प्रेस का अस्तित्व जब तक कि उन्हें इंडियन एक्सप्रेस मदुरै (पी) लिमिटेड में काम पर नहीं रखा गया था, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता कि कंपनी जब चाहे रोटरी प्रेस का उपयोग कर सकती थी। हमें चीजों का आकलन इस आधार पर करना है कि क्या किया गया था, न कि इस आधार पर कि क्या किया जा सकता था।

पुनः यह परिस्थिति कि इनमें से कुछ पत्रिकाएँ मई 1959 के कुछ समय बाद नई घोषणाओं आंध्र प्रभा लिमिटेड के तहत प्रकाशित हुईं। आंध्र प्रभा (पी) लिमिटेड और इंडियन एक्सप्रेस मदुरै (पी) लिमिटेड की ओर से क्रमशः प्रकाशकों द्वारा किया गया अप्रैल 1959 में कंपनी के उपक्रम को बंद करने के खिलाफ निष्कर्ष पर विचार किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण ने इस तथ्य पर कुछ भरोसा किया है कि रामनाथ गोयनका ने रुपये की राशि अग्रिम रूप से स्वीकार की थी। 3 मदुरै कंपनी को लाखों रुपये के साथ-साथ कुल रु। 27 दिसंबर 1960 के अंत तक दो सहायक कंपनियों (विजयवाड़ा और मदुरै में) सहित अन्य कंपनियों को लाख। न्यायाधिकरण ने पाया कि (ए) अंततः इंडियन एक्सप्रेस बॉम्बे लिमिटेड ने आंध्र प्रभा (पी) लिमिटेड और इंडियन एक्स प्रेस मदुरै (पी) लिमिटेड के सभी शेयरों का पीछा किया और 1960 के अंत में एक सार्वजनिक कंपनी बन गईः (ख) कंपनी के सार्वजनिक कंपनी बनने से

पहले, रामनाथ गोयनका और उनके परिवार के सदस्यों के पास 4200 में से 4000 शेयर थेः (ग) मई 1959 तक कंपनी जिसके पास एक ही प्रबंधन द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों के पूरे समूह का स्वामित्व था, तीन शाखा कार्यालयों में एक दिल्ली में, दूसरा मदुरै में और तीसरा बॉम्बे में। विभाजन के परिणामस्वरूप, स्थिति यह थी कि दिल्ली में एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (पी) लिमिटेड ने दिल्ली प्रकाशनों को लिया, इंडियन एक्सप्रेस बॉम्बे (पी) लिमिटेड ने बॉम्बे से कंपनी द्वारा प्रकाशित प्रकाशनों को लिया, इंडियन एक्सप्रेस मदुरै (पी) लिमिटेड ने मदुरै और आंध्र प्रभा (पी) लिमिटेड से जारी प्रकाशनों को लिया। विजयवाड़ा ने दो तेलुगु प्रकाशनों को लिया। न्यायाधिकरण के अनुसार "यह केवल मदुरै कंपनी और विजयवाड़ा कंपनी थी जो मई 1959 के बाद उनके द्वारा अधिग्रहित कागजातों को छापने और प्रकाशित करने के लिए मूल कंपनी के समर्थन पर निर्भर थी।" न्यायाधिकरण ने आगे पाया कि यह स्थिति मई 1959 के बाद कुछ समय के लिए जारी रही क्योंकि "(1) टेलीप्रिंटर सेवा।एक्सप्रेस एस्टेट भवन में स्थापित माउंट रोड जारी रहा अक्टूबर 1959 के अंत तक और नौ परिपथों में से उपयोग किया जाएगा टेलीप्रिंटर सेवा में शामिल, सात के माध्यम से रूट किया गया था मद्रास और इन्हें मदुरै कंपनी को आवंटित किया गया था। 1 नवंबर 1959 से शुरू होने वाली तीन महीने की अवधि। (2) प्रसंस्करण विभाग में उपयोग की जाने वाली फोटोग्राफिक सामग्री अक्टूबर

1959 तक कंपनी द्वारा बनाए रखा गया था जिसे सार्वजनिक कंपनी ने टू डॉटर कॉम के लाभ के लिए खरीदा था।(3) तीस-एक रिपोर्टर सहित कंपनी के दो पूर्व कर्मचारियों को अप्रैल के बाद कंपनी की सेवा में बरकरार रखा गया था।1959 ; (4) आयुक्त को कोई सूचना नहीं भेजी गई थी या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत काम करने वाले 700 श्रमिकों के रोजगार की समाप्ति के अन्य सक्षम प्राधिकारी और पत्रकार, और (5) अप्रैल 1959 के बाद दो सहायक कंपनियों के लिए एक आम विज्ञापन विभाग बनाए रखा गया था एक्सप्रेस एस्टेट भवन जैसा कि दिसंबर 1959 में जारी किए गए कुछ परिपत्रों से देखा जा सकता है।

इन सब से न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि निलंबन व्यवसाय शुरुआत में तालाबंदी का एक हिस्सा था बन गया। केवल और एक वास्तविक बंद अक्टूबर-नवंबर, 1959 में बन गया। हमारे सामने, श्री मोहन कुमारमंगलम द्वारा उपरोक्त कुछ कारकों पर निर्भरता रखी गई थी और उनके तर्क का मुख्य मुद्दा यह था कि वास्तव में मूल कंपनी ने अन्य कंपनियों को शुरू किया और वित्तीय रूप से मदद की जो वास्तव में मूल कंपनी के लिए बेनामीदार थीं। हमें नहीं लगता कि औद्योगिक कानून में भी एक नई कंपनी जो एक स्वतंत्र कानूनी इकाई है, उसे किसी अन्य पुराने संगठन के लिए बेनामीदार कहा जा सकता है क्योंकि दोनों कंपनियों में एक व्यक्ति या व्यक्तियों का परिवार था जो दोनों कंपनियों के भाग्य का

मार्गदर्शन कर सकता था। एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (पी) लिमिटेड को बाद में एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया और विजयवाड़ा और मदुरै कंपनियों के संबंधों को सहायक कंपनियों या कंपनी के बेनामीदारों के रूप में वर्णित करना उचित नहीं होगा। हमें यह ध्यान रखना होगा कि कंपनी यानी एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स (पी) लिमिटेड अप्रैल 1959 में समाप्त नहीं हुई थी। इसने केवल कई समाचार पत्रों और साप्ताहिक समाचार पत्रों के प्रकाशन के अपने उपक्रम को बंद कर दिया। अप्रैल 1959 के बाद इसके हाथों में बहुत मूल्यवान संपत्ति थी और संपत्ति की देखभाल के लिए कुछ व्यक्तियों को सेवा में रखना पड़ा। यह तथ्य कि उनमें से एक रिपोर्टर था, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि कंपनी ने अपना व्यवसाय बंद नहीं किया था, लेकिन जब चाहे इसे उठा सकती थी। इसके अलावा, भविष्य निधि अधिकारियों को सूचित करने में विफलता एक चूक थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि कर्मचारी कंपनी की सेवा में बने रहे या जैसे ही वे रामनाथ गोयनका के अधीन हो गए, उन्हें इसकी सेवा में वापस ले लिया जाना था। टेलीप्रिंटर सेवा के संबंध में, हमें बताया गया था कि इसका भुगतान एक निश्चित तिथि तक किया गया था और यह तथ्य कि मदुरै और विजयवाड़ा कंपनियों ने अक्टूबर 1959 के अंत तक टेलीप्रिंटर सेवा का उपयोग किया था, इस निष्कर्ष को सही ठहराता है कि कंपनी ने

यदि आवश्यक हो तो अपने स्वयं के उपयोग के लिए टेलीप्रिंटर सेवा को बनाए रखा।

सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, कंपनी का कारोबार 29 अप्रैल 1959 से बंद कर दिया गया था और बंद करने के पीछे जो भी मकसद रहा हो, वह अप्रैल 1959 से प्रभावी था और हमें ट्रिब्यूनल के साथ बंद करने का कोई कारण नहीं दिखता है कि बंद नवंबर 1959 में किस समय प्रभावी हुआ।

कर्मचारियों की ओर से अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के लिए आवेदन किया गया है. इस एप्लिकेशन में अवार्ड के प्रकाशन के बाद हुई घटनाओं पर भरोसा किया गया है, जिससे पता चलता है कि मद्रास से प्रकाशनों को बंद करना एक मात्र छलावा था और कर्मचारियों को डराने-धमकाने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई एक युक्ति थी और वह प्रकाशन अवार्ड के प्रकाशन के तुरंत बाद समाचार पत्र शुरू हो गए थे। हम इस मामले में ज्यादा विस्तार से जाना जरूरी नहीं समझते क्योंकि बीच में चार साल से ज्यादा का ब्रेक आ गया था और इतना समय बीतने के बाद कंपनी क्या करती है? यह पता लगाने के लिए कि क्या बंद वास्तविक था या केवल एक उपकरण था, जैसा कि कर्मचारियों द्वारा सुझाया गया था, अवधि पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिए। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि रामनाथ गोयनका की योजना

समाचार पत्र प्रकाशन के व्यवसाय को पूरी तरह से छोड़ने की नहीं थी बल्कि वह अपने व्यवसाय को विभिन्न स्थानों पर वितरित करना चाहते थे। इस तरह की योजना के पीछे का उद्देश्य जो भी हो, उन्होंने अवार्ड के प्रकाशन के बाद ही उस योजना को लागू किया था और इससे हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि बंद एक काल्पनिक था। हमारे विचार में, हड़ताल उचित नहीं थी और प्रबंधन 29 अप्रैल, 1959 को उपक्रम को बंद करने का हकदार था।

परिणामस्वरूप, इस आवेदन पर कोई आदेश नहीं होगा। कंपनियों की अपील स्वीकार की जाती है और दूसरे मुद्दे पर निष्कर्ष और अवार्ड को रद्द कर दिया जाता है। उपर्युक्त के दृष्टिगत कर्मकारों की अपील क्रमांक 9 सन् 1966 को खारिज करना होगा। सभी अपीलों में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

वीपीएस

1966 की अपील संख्या 91 खारिज और 1965 की संख्या 1078 और 1079 स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक मुकेश कुमार मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।